

पंचायती राज में राजकोषीय हस्तांतरण

यह एडिटरियल 21/02/2024 को 'द हट्टि' में प्रकाशित "[Having panchayats as self-governing institutions](#)" लेख पर आधारित है। इसमें पंचायतों द्वारा आत्मनिर्भरता प्राप्त करने और अपने स्वयं के वित्तीय संसाधनों पर भरोसा करने के महत्त्व के बारे में नरिवाचति प्रतनिधियों और आम लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है।

प्रलिस के लयि:

[स्थानीय सरकारें](#), [73वाँ संवैधानिक संशोधन](#), [74वाँ संशोधन अधनियम \(1992\)](#), [पंचायती राज संस्थाएँ](#), [स्थानीय स्वशासन](#), [भारतीय रजिस्व बैंक](#), [राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना](#)।

मेन्स के लयि:

भारत में पंचायतों का कामकाज, सरकारी नीतयिँ और हस्तकषेप

[73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन अधनियम](#) को लागू हुए तीन दशक बीत चुके हैं, जनिके माध्यम से परकिल्पना की गई थी कि भारत में स्थानीय नकिय स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करेंगे। इसके अनुसरण में, ग्रामीण स्थानीय सरकारों को सुदृढ़ करने के लयि वर्ष 2004 में पंचायती राज मंत्रालय का गठन कयिा गया।

इस संवैधानिक संशोधन ने राजकोषीय हस्तांतरण पर वशिषिट वविरण प्रदान कयिा है जसिमें स्वयं के राजस्व का सृजन करना शामिल है। केंद्रीय अधनियम की रूपरेखा पर वभिन्न राज्यों के पंचायती राज अधनियमों द्वारा कराधान एवं संग्रह के प्रावधान कयिे गए। इन अधनियमों के प्रावधानों के आधार पर पंचायतों ने अपने स्वयं के संसाधन सृजति करने के अधिकितम प्रयास कयिे।

73वें और 74वें संशोधन की मुख्य बातें क्या हैं?

परचिय:

- इन संशोधनों ने संवैधान में दो नए भाग जोड़े, अर्थात् 73वें संशोधन द्वारा भाग IX—जसिका शीर्षक 'पंचायत' है और 74वें संशोधन में भाग IXA—जसिका शीर्षक 'नगरपालिकाएँ' है।
- लोकतांत्रिके व्यवस्था की बुनयादी इकाइयों के रूप में ग्राम सभा (ग्राम में) और वार्ड समतियिँ (नगरपालिकाओं में) का गठन कयिा गया जनिमें मतदाता के रूप में पंजीकृत सभी वयस्क नागरिक भागीदारी करते हैं।
- प्रत्येक राज्य में (20 लाख से कम आबादी वाले राज्यों को छोड़कर) ग्राम, मध्यवर्ती स्तर (प्रखंड/तालुक/मंडल) और ज़िला स्तर पर पंचायतों की त्रि-स्तरीय प्रणाली अपनाई गई (अनुच्छेद 243B)।
- सभी स्तरों पर सीटें प्रत्यक्ष चुनाव से भरी जानी हैं (अनुच्छेद 243C(2))।

आरक्षण का प्रावधान:

- [अनुसूचति जाति\(SC\)](#) एवं [अनुसूचति जनजाति\(ST\)](#) के लयि सीटों के आरक्षण की व्यवस्था की गई है और सभी स्तरों पर पंचायतों के अध्यक्ष के पद भी SC एवं ST के लयि उनकी आबादी के अनुपात में आरक्षति कयिे जा सकते हैं।
- कुल सीटों की एक तहिाई सीटें महिलाओं के लयि आरक्षति की जाएँगी।
- SC और ST के लयि आरक्षति सीटों में से भी एक तहिाई सीटें उनकी महिलाओं के लयि आरक्षति होंगी।
- सभी स्तरों पर अध्यक्षों के पद के एक तहिाई महिलाओं के लयि आरक्षति होंगे (अनुच्छेद 243D)।

कार्यकाल:

- सभी के लयि समान रूप से पाँच वर्ष का कार्यकाल होगा और कार्यकाल की समाप्ति से पहले नए नकियों के गठन के लयि चुनाव संपन्न करा लयि जाएँगे।
- कार्यकाल से पूरव वधितन की स्थति में छह माह के भीतर अनविर्य रूप से चुनाव संपन्न करा लयि जाएँगे (अनुच्छेद 243E)।
- मतदाता सूची के अधीक्षण, नरिदेशन और नरितरण के लयि प्रत्येक राज्य में स्वतंत्र [नरिवाचन आयोग](#) होगा (अनुच्छेद 243K)।

वकिसात्तमक योजना नरिमाण:

- ग्यारहवीं अनुसूची में वरगति वषियों सहति पंचायतों के वभिन्न स्तरों पर वधि द्वारा सौपे गए वषियों के संबंध में पंचायतें आर्थिक वकिस एवं सामाजिक न्याय के लयि योजनाएँ तैयार करेंगी (अनुच्छेद 243G)।

- 74वाँ संशोधन पंचायतों और नगरपालिकाओं द्वारा तैयार की गई योजनाओं को समेकित करने के लिये एक ज़िला योजना समिति का प्रावधान करता है (अनुच्छेद 243ZD)।
- ग्यारहवीं अनुसूची पंचायती राज नकियों के दायरे में 29 कार्यों को रखती है।
- **राजस्व और वित्त:**
 - राज्य सरकारों से बजटीय आवंटन, कुछ करों से प्राप्त राजस्व में हसिसेदारी, स्वयं द्वारा जुटाए गए राजस्व का संग्रह एवं प्रतधारण, केंद्र सरकार के कार्यक्रम एवं अनुदान, केंद्रीय वित्त आयोग अनुदान (अनुच्छेद 243H)।
 - एक **वित्त आयोग** की स्थापना की जाएगी जिसके आधार पर पंचायतों और नगरपालिकाओं के लिये पर्याप्त वित्तीय संसाधन सुनिश्चि किये जाएँगे (अनुच्छेद 243I)।

पंचायती राज संस्थाओं के वित्त की वर्तमान स्थिति क्या है?

- **राजस्व संबंधी आँकड़े:**
 - RBI के अनुसार, वित्त वर्ष 2022-23 में पंचायतों ने कुल 35,354 करोड़ रुपए का राजस्व दर्ज किये।
 - हालाँकि, उनके स्वयं के कर राजस्व से केवल 737 करोड़ रुपए उत्पन्न हुए, जो पेशे एवं व्यापार पर कर, भूमि राजस्व, स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क, संपत्तिकर और सेवा कर के माध्यम से अर्जित हुए।
 - गैर-कर राजस्व 1,494 करोड़ रुपए रहा, जो मुख्य रूप से ब्याज भुगतान और पंचायती राज कार्यक्रमों से प्राप्त हुआ।
 - उल्लेखनीय है कि पंचायतों को केंद्र सरकार से 24,699 करोड़ रुपए और राज्य सरकारों से 8,148 करोड़ रुपए का अनुदान प्राप्त हुआ।
- **राजस्व प्रतपंचायत:**
 - औसतन प्रत्येक पंचायत ने अपने स्वयं के कर राजस्व से केवल 21,000 रुपए और गैर-कर राजस्व से 73,000 रुपए अर्जित किये।
 - इसके विपरीत, केंद्र सरकार से प्राप्त अनुदान प्रतपंचायत लगभग 17 लाख रुपए रहा, जबकि राज्य सरकार का अनुदान प्रतपंचायत 3.25 लाख रुपए से अधिक रहा।
- **राज्य राजस्व हसिसेदारी और अंतर-राज्य असमानताएँ:**
 - संबद्ध राज्य के राजस्व में पंचायतों की हसिसेदारी न्यूनतम बनी हुई है।
 - उदाहरण के लिये, आंध्र प्रदेश में पंचायतों की राजस्व प्राप्तियाँ राज्य के स्वयं के राजस्व का केवल 0.1% है, जबकि उत्तर प्रदेश में यह 2.5% है जो भारत के सभी राज्यों में सर्वाधिक है।
 - प्रतपंचायत अर्जित औसत राजस्व के संबंध में राज्यों में व्यापक भिन्नताएँ मौजूद हैं।
 - केरल और पश्चिम बंगाल क्रमशः 60 लाख रुपए और 57 लाख रुपए प्रतपंचायत के औसत राजस्व के साथ सबसे आगे हैं।
 - असम, बहार, कर्नाटक, ओडिशा, सिकिम और तमिलनाडु में प्रतपंचायत राजस्व 30 लाख रुपए से अधिक था।
 - आंध्र प्रदेश, हरियाणा, मजोरम, पंजाब और उत्तराखंड जैसे राज्यों का औसत राजस्व प्रतपंचायत 6 लाख रुपए से भी कम है।

Chart 1 | The chart shows the revenue receipts of panchayats in 2022-23. Figures in %

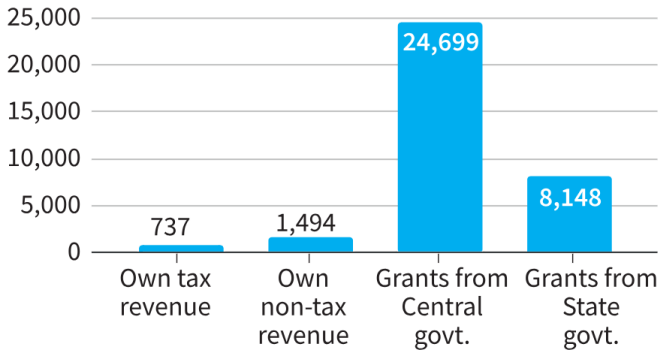


Chart 2 | The chart shows the average revenue per panchayat in 2022-23. Figures in ₹ thousand

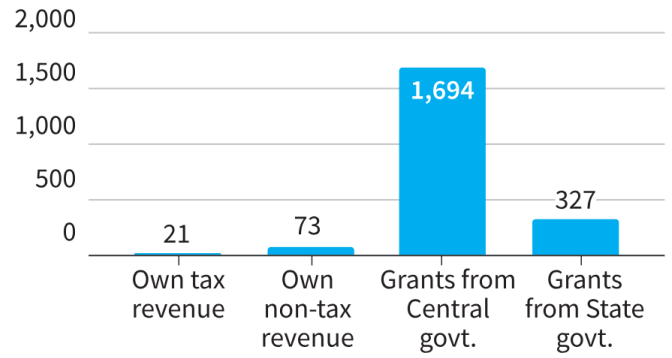


Chart 3 | The chart shows the revenue per panchayat in percentage terms in 2022-23.

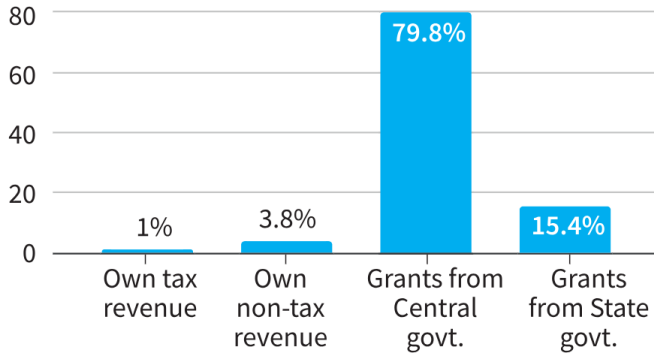


Chart 4 | The chart shows the average revenue per panchayat across States in 2022-23. Figures in ₹ lakh.

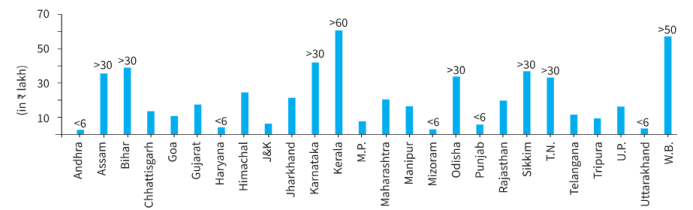
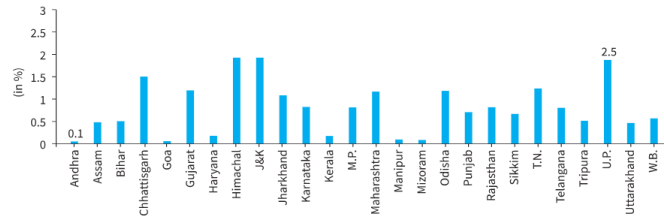


Chart 5 | The chart shows the revenue of panchayats as a share of the State's own revenue in 2022-2023. Figures in %.



//

पंचायतों द्वारा आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की आवश्यकता क्यों है?

हाल ही में RBI द्वारा वित्त वर्ष 22-23 के लिये जारी 'पंचायती राज संस्थाओं का वित्त' शीर्षक रिपोर्ट भारत में पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) की वित्तीय गतिशीलता पर प्रकाश डालती है।

■ अनुदान पर अत्यधिक नरिभरता:

- पंचायतें करों के माध्यम से राजस्व का केवल 1% अर्जति करती हैं, शेष भाग राज्य और केंद्र से अनुदान के रूप में जुटाया जाता है। यह विशेष रूप से बताता है कि इन्हें 80% राजस्व केंद्र से और 15% राज्यों से प्राप्त होता है।
- यह विकेंद्रीकरण के समर्थकों के लिये आँखें खोलने वाली बात है क्योंकि इसका परिणाम यह है कि हिस्तांतरण पहलों की शुरुआत के 30 वर्षों के बाद भी पंचायतों द्वारा जुटाया जा रहा राजस्व बहुत कम है।

■ राज्यों के बीच भिन्नताएँ:

- जब हस्तांतरण की स्थिति के विश्लेषण की बात आती है तो यह स्पष्ट होता है कि कुछ राज्य आगे निकल गए हैं जबकि कई पीछे रह गए हैं। विकेंद्रीकरण के प्रति राज्य सरकारों की प्रतिबद्धता PRIs को ज़मीनी स्तर पर एक प्रभावी स्थानीय शासन तंत्र बनाने के लिये महत्वपूर्ण रही है।
 - कई राज्यों में ग्राम पंचायतों के पास कर संग्रहण का अधिकार नहीं है, जबकि कई अन्य राज्यों में मध्यवर्ती और ज़िला पंचायतों को कर संग्रहण की ज़िम्मेदारी नहीं सौंपी गई है।
 - जबकि ग्राम पंचायतें अपने स्वयं के करों का 89% एकत्र करती हैं, मध्यवर्ती पंचायतें महज 7% और ज़िला पंचायतें महज 5% ही एकत्र करती हैं। समान हस्तिसेदारी सुनिश्चित करने के लिये संपूर्ण त्रि-स्तरीय पंचायतों हेतु राजस्व के अपने स्रोत (Own Source of Revenue- OSR) का सीमांकन करने की आवश्यकता है।

■ स्वयं की आय सृजति करने के प्रति सामान्य अरुचि:

- केंद्रीय वित्त आयोग (CFC) के अनुदान के आवंटन में वृद्धि के साथ, पंचायतें OSR के संग्रहण में कम रुचि दिखा रही हैं। 10वें और 11वें CFC से ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिये आवंटन क्रमशः 4,380 करोड़ रुपए और 8,000 करोड़ रुपए रहा था।
 - लेकिन 14वें और 15वें CFC द्वारा प्रदत्त अनुदान में भारी वृद्धि हुई जहाँ यह क्रमशः 2,00,202 करोड़ रुपए और 2,80,733 करोड़ रुपए रहा।
 - वर्ष 2018-19 में 3,12,075 लाख रुपए का कर संग्रहण हुआ जो वर्ष 2021-2022 में घटकर 2,71,386 लाख रुपए हो गया। इसी अवधि में संग्रहित गैर-कर राजस्व 2,33,863 लाख रुपए और 2,09,864 लाख रुपए रहा।

■ राज्य सरकारों द्वारा प्रोत्साहन :

- एक समय पंचायतें बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति की अपनी प्रतिबद्धता के लिये OSR जुटाने की होड़ में रहती थीं। वह होड़ अब विभिन्न वित्त आयोगों के माध्यम से आवंटन एवं प्रतिपूर्ति पर नरिभरता से प्रतिस्थापित हो गया है।
- कुछ राज्यों ने संगत अनुदान प्रदान करने के माध्यम से प्रोत्साहन (incentivisation) की नीति अपनाई है, लेकिन इसे बहुत कम लागू किया गया। पंचायतों को डिफॉल्टरों को दंडित करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि उनका मानना है कि OSR को एक आय के रूप में नहीं माना गया है जो पंचायत वित्त से जुड़ा हुआ है।

■ 'फ्रीबीज़ कल्चर' के कारण बाधाएँ:

- राजस्व बढ़ाने के हर संकषम कारक के बावजूद, पंचायतें संसाधन जुटाने में कई बाधाओं का सामना करती हैं; समाज में व्याप्त मुफ्तखोरी की संस्कृति (Freebies Culture) करों के भुगतान में व्याप्त उदासीनता का कारण है। नरिवाचति प्रतिनिधियों को लगता है कि कर अधरिपण से उनकी लोकप्रियता पर प्रतिक्ल प्रभाव पड़ेगा।

PRIs के वित्तीय संसाधनों को बढ़ावा देने के लिये आवश्यक सुझाव क्या हैं?

■ विशेषज्ञ समिति की रपिर्ट:

- पंचायती राज मंत्रालय द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति की रपिर्ट राज्य अधिनियमों के विवरण पर वस्तितार से चर्चा करती है जिसमें कर एवं गैर-कर राजस्व शामिल किया गया है जिससे पंचायतों द्वारा संग्रहित एवं उपयोग किया जा सकता है।
 - संपत्ति कर, भूमि राजस्व पर उपकर, अतिरिक्त स्टॉप शुल्क पर अधिभार, टोल, पेशे पर कर, वजिजापन, जल एवं स्वच्छता और प्रकाश व्यवस्था के लिये उपयोगकर्त्ता शुल्क ऐसे प्रमुख OSRs हैं जहाँ पंचायतें अधिकतम आय अर्जति कर सकती हैं।

■ अनुकूल वातावरण की स्थापना करना:

- पंचायतों से अपेक्षा की जाती है कि वे उचित वित्तीय वनियमनों को लागू कर कराराधान के लिये अनुकूल वातावरण स्थापित करें। इसमें कर एवं गैर-कर आधारों के संबंध में नरिणय लेना, उनकी दरें नरिधारित करना, आवधिक संशोधन के लिये प्रावधान स्थापित करना, छूट कषेत्रों को परिभाषित करना और संग्रह के लिये प्रभावी कर प्रबंधन एवं प्रवर्तन कानून बनाना शामिल हैं।

■ गैर-कर राजस्व के लिये स्रोतों का वविधीकरण:

- गैर-कर राजस्व की विशाल संभावनाओं में शुल्क, करिया और नविश बकिरी से प्राप्त आय तथा करिया प्रभार (hires charges) एवं प्राप्तियाँ शामिल हैं। ऐसी नवोन्मेषी परियोजनाएँ भी हैं जो OSR सृजति कर सकती हैं। इसमें ग्रामीण व्यापार केंद्रों, नवोन्मेषी वाणज्यिक उद्यमों, नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं, कार्बन क्रेडिट, **कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR)** नधि और दान शामिल हैं।

■ स्थानीय संसाधनों का लाभ उठाना:

- राजस्व सृजन के लिये स्थानीय संसाधनों का लाभ उठाकर ज़मीनी स्तर पर आत्मनरिभरता प्राप्त करने और सतत् विकास को बढ़ावा देने में ग्राम सभाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है।
 - वे कृषि और पर्यटन से लेकर लघु-स्तरीय उद्योगों तक की राजस्व-सृजन पहलों के योजना नरिमाण, नरिणयन और कार्यान्वयन में संलग्न हो सकते हैं।
 - उनके पास कर, शुल्क एवं लेवी अधरिपति करने और प्राप्त धन को स्थानीय विकास परियोजनाओं, सार्वजनिक सेवाओं एवं सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों की ओर नरिदेशित करने का प्राधिकार है।

■ भागीदारी को बढ़ावा देना:

- पारदर्शी वित्तीय प्रबंधन और समावेशी भागीदारी के माध्यम से, ग्राम सभाएँ जवाबदेही सुनिश्चित करती हैं तथा सामुदायिक भरोसे को बढ़ावा देती हैं; इस प्रकार, अंततः ग्रामों को आर्थिक रूप से स्वतंत्र एवं प्रत्यास्थ बनने के लिये सशक्त करती हैं।
- इस प्रकार, ग्राम सभाओं को उद्यमशीलता को बढ़ावा देने और राजस्व सृजन प्रयासों की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिये **हतिधारकों**

के साथ भागीदारी को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।

■ **RBI की सफ़ाई:**

- RBI वृहत वक़िंदरीकरण को बढ़ावा देने और स्थानीय नेताओं एवं अधिकारियों को सशक्त करने का सुझाव देता है। यह पंचायती राज की वक़ितीय स्वायत्तता एवं संवहनीयता को बढ़ाने के उपायों की वक़ालत करता है।
- रपिर्ट में इस बात पर बल दिया गया है कि PRIs पारदर्शी बजटगि, राजकोषीय अनुशासन, वक़िस प्रथमक़िता में सामुदायिक भागीदारी, कर्मचारी प्रशक़िषण और कठोर नगिरानी एवं मूलयांकन को अपनाकर संसाधन उपयोग को बेहतर बना सकते हैं।
- इसके अतरिक़ित, इसने पंचायती राज संस्थाओं के कार्यों के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने और प्रभावी स्थानीय शासन के लयि नागरिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।

■ **नरिवाचति प्रतनिधियों और आम लोगों को शक़िषति करना:**

- पंचायतों को स्वशासी संस्थाओं के रूप में वक़िसति करने के लयि राजस्व जुटाने के महत्त्व पर नरिवाचति प्रतनिधियों और आम लोगों को शक़िषति करने की आवश्यकता है।
 - अंततः, अनुदान के लयि 'डरिपेंडेंसी सडिरोम' को कम करना होगा और समय के साथ पंचायतें अपने स्वयं के संसाधनों पर अस्तति्व बनाए रखने में सक़्षम होंगी। पंचायतें ऐसी स्थतितिभी प्राप्त कर सकती हैं जब शासन के सभी स्तरों पर समरपति प्रयास हों, जसिमें राज्य-स्तर और केंद्रीय स्तर भी शामिल हैं।

संबंधति पहले कौन-सी हैं?

■ **स्वामतिव योजना:**

- प्रत्येक ग्रामीण परिवार के स्वामी को 'स्वामतिव का रक़िर्ड' प्रदान कर ग्रामीण भारत की आरथक़ि प्रगतिको सक़्षम करने के लयि [राष्ट्रीय पंचायती राज दविस \(2020\)](#) के अवसर पर [ग्रामों का सरवेक़षण और ग्रामीण क़्षेत्रों में उननत प्रौद्योगिक़ि से मानचतिरण](#) (Survey of Villages and Mapping with Improved Technology in Village Areas- SVAMITVA) योजना, यानी स्वामतिव योजना शुरू की गई।

■ **ई-ग्राम स्वराज ई-वक़ितीय प्रबंधन प्रणाली:**

- ई-ग्राम स्वराज [पंचायती राज](#) के लयि एक सरलीकृत कार्य आधारति लेखांकन ऐप (Simplified Work Based Accounting Application) है।

■ **परसिपत्तियों की जयि-टैगि:**

- पंचायती राज मंत्रालय ने 'mActionSoft' वक़िसति कयिा है, जो उन कार्यों के लयि [जयि-टैग](#) (Geo-Tags, i.e. GPS Coordinates) के साथ फोटो खींचने में मदद करने के लयि एक मोबाइल-बेस्ड सोल्यूशन है, जसिमें आउटपुट के रूप में परसिपत्तित्ति होती है।

■ **सटिज़न चार्टर:**

- सेवाओं के मानक के संबंध में अपने नागरिकों के प्रतPRIs की प्रतबिदधता पर ध्यान केंद्रति करने के लयि पंचायती राज मंत्रालय ने 'मेरी पंचायत मेरा अधिकार - जन सेवाएँ हमारे द्वार' के नारे के साथ सटिज़न चार्टर दसतवेज़ों को अपलोड करने के लयि एक मंच प्रदान कयिा है।

■ **संशोधति राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभयान (वर्ष 2022-23 से 2025-26):**

- [संशोधति राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभयान योजना](#) का प्रथमक़ि उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं को स्थानीय स्वशासन के सकरयि केंद्रों में बदलना है जहाँ [ज़मीनी स्तर पर सतत वक़िस लक़्ष्यों के स्थानीयकरण](#) (Localisation of Sustainable Development Goals- LSDGs) पर वशिष बल दिया गया है। इसे एक वशिषगत दृष्टिकोण के माध्यम से प्राप्त कयिा जाना है जसिमें केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य लाइन वभिगों और वभिनिन हतिधारकों के समन्वति प्रयास शामिल होंगे। यह रणनीति 'समग्र सरकार और समग्र समाज' (Whole of Government and Whole of Society) के व्यापक दृष्टिकोण पर आधारति होगी।

नषिक़रष

संवैधानक़ि संशोधनों के अनुसार राजकोषीय हसतांतरण में स्वयं का राजस्व सृजति करना शामिल है, जहाँ पंचायतें अपने संसाधनों को अधिकितम करने का प्रयास करेंगी। हालाँकि, हाल के आँकड़ों से पता चलता है कि पंचायतें करों के माध्यम से केवल 1% राजस्व ही अरजति करती हैं, जो राज्य और केंद्र से प्राप्त अनुदान पर नरितर नरिभरता को उजागर करता है। OSR पर रपिर्ट पंचायतों के लयि संपत्तति कर, उपयोगकर्त्ता शुल्क और नवोनमेषी परयोजनाओं जैसे वभिनिन तरीकों से आय अरजति करने की संभावना पर बल देती है। 'फ़रीबीज़ कल्चर' और कर लगाने की अनविछा जैसी चुनौतियों के बावजूद, नरिवाचति प्रतनिधियों और आम लोगों को राजस्व सृजन के महत्त्व पर शक़िषति करने से पंचायतों को वक़ितीय रूप से स्वतंत्र एवं आत्मनरिभर बनाने में मदद मलि सकती है।

अभयास प्रश्न: अपने स्वयं के राजस्व सृजति करने में पंचायती राज संस्थाओं के समक़्ष वदियमान चुनौतियों की चरचा कीजयि और उनकी वक़ितीय स्वायत्तता बढ़ाने के उपाय सुझाइये।

UPSC सवलि सेवा परीक़ा, वगित वर्ष के प्रश्न (PYQs)

????????????

प्रश्न. स्थानीय स्वशासन कसि गुण की सर्वाधिक सटीक व्याख्या करता है? (2017)

- (a) संघवाद
- (b) लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण
- (c) प्रशासनिक प्रतनिधिर्मिडल
- (d) प्रत्यक्ष लोकतंत्र

उत्तर: (b)

प्रश्न 2. पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य नमिनलखिति में से कसि सुनिश्चति करना है? (2015)

1. विकास में जनभागीदारी
2. राजनीतिक जवाबदेही
3. लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण
4. वत्तीय गतशीलता

नीचे दयि गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनयि

- (a) केवल 1, 2 और 3
- (b) केवल 2 और 4
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर: (c)

?????

प्रश्न 1. स्थानीय सरकार के एक भाग के रूप में भारत में पंचायत प्रणाली के महत्त्व का आकलन कीजयि । विकास परयोजनाओं के वत्तिपोषण के लएि पंचायतें सरकारी अनुदानों के अलावा कनि स्रोतों की तलाश कर सकती हैं? (वर्ष 2018)

प्रश्न 2. आपकी राय में, भारत में सत्ता के विकेंद्रीकरण ने ज़मीनी स्तर पर शासन के परदृश्य को कसि हद तक बदल दयिा है? (वर्ष 2022)